भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1481
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आंध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना</u>

1481. श्री बी. के. पार्थसारथीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के घटक-ए की स्थापना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में बंजर/परती भूमि पर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों (आरईपीपी) की स्थापना के लिए आवंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में घटक-ए के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें स्थापित विद्युत संयंत्रों की संख्या और उनकी क्षमता शामिल है, और

(घ) आंध्र प्रदेश में व्यक्तिगत किसानों, किसानों के समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों, एफपीओ और डब्ल्यूयूए के लिए स्थानीय डिस्कॉम को निश्चित टैरिफ पर उत्पादित बिजली बेचने की क्या व्यवस्था है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): पीएम-कुसुम योजना के घटक-क का उद्देश्य, किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना है।

डिस्कॉम्स संभावित किसानों से रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, जहाँ वे निर्धारित प्रारूप में सौर विद्युत संयत्र स्थापित करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, सौर विद्युत संयंत्र किसानों द्वारा अपनी भूमि पर स्वयं द्वारा सीधे तौर पर या किसानों के समूह/सहकारी समितियों/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) के साथ साझेदारी में या किसी डेवलपर के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।

पीएम-कुसुम योजना एक मांग आधारित योजना है और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर आवंटन किए जाते हैं। पीएम-कुसुम योजना के किसी भी घटक के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, राज्य को कोई आवंटन नहीं किया गया है।

*****